THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): Sir, I would like to humbly submit, since I was named by the hon. Member.....(*Interruptions*)... Sir, since I was named by the hon. Member, I would like to very humbly put forth.. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Time over. ...(*Interruptions*)... Later. ...(*Interruptions*)... Question Hour. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I have to give an explanation now. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is time for Question Hour. ...(*Interruptions*)... It is time for Question Hour. ...(*Interruptions*)...

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Mr. Agarwal was not a Rajya Sabha Member from that nodal district. I had to give respect to the Rajya Sabha Member from that nodal district. In fact, his ...(*Interruptions*)... is very much there on the plaque. ...(*Interruptions*)...

12.00 NOON

MR. CHAIRMAN *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

National Small Industries Corporation in Gujarat

*136. SHRI AHMED PATEL: Will the Minister of MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES be pleased to state:

(a) the details of works being undertaken by the National Small Industries Corporation in Gujarat;

(b) the details of funds sanctioned and utilized by the NSIC in Gujarat in each of the past three years including the current year; and

(c) number of people who became entrepreneurs in Gujarat with the help of NSIC during the said period?

THE MINISTER OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SHRI KALRAJ MISHRA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC) operates in Gujarat through its offices at Ahmadabad, Vadodara, Surat, Rajkot and Nadiad. It provides

Support for development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through various schemes and services such as raw material distribution, credit support for raw materials procurement, tender and consortia marketing and technical assistance to MSMEs. It also implements two Schemes of the Ministry namely Performance and Credit Rating (PCR) Scheme and Marketing Assistance Scheme (MAS).

(b) There is no specific allocation of funds for any State (including the State of Gujarat). However, NSIC provided ₹ 50.80 crore in 2013-14, ₹ 116.16 crore in 2014-15 and ₹ 89.16 crore in 2015-16 (up to 29 Feb, 2016) under credit support in Gujarat. It also distributed 67093 MTs of raw materials in 2013-14, 60641 MTs in 2014-15 and 76438 MTs in 2015-16 to MSME units in Gujarat. Under PCR Scheme, 3358 units, 3131 units and 1312 units have been rated in Gujarat during 2013-14, 2014-15 and 2015-16 (up to 29 Feb, 2016) respectively. Under Marketing Assistance Scheme (MAS), 268 units, 85 units and 53 units have been assisted in Gujarat during 2013-14, 2014-15 and 2015-16 (up to 29 Feb, 2016) respectively.

(c) Only recently, NSIC has started one Livelihood Business Incubation (LBI) at Rajkot on 18th December, 2015 to impart Entrepreneurship Development Training and handholding support to the youth under ASPIRE (A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship) Scheme. However, four Training cum-Incubation Centres (TIC) have already been working under PPP mode in Anand, Vadodara (two) and Gandhi Nagar. At these Centres the trainees are encouraged to take wage/self employment. No budgetary support is being provided to these PPP Centres.

MR. CHAIRMAN: Question Hour. ...(*Interruptions*)... Question 136.

श्री अहमद पटेलः सर, Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) की स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक व दयनीय है। हम बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स की चिन्ता तो करते हैं, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि पिछले दो साल में MSMEs के कितने सिक यूनिट्स सामने आए हैं? उनको रिवाइव करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हम Non-Performing Assets (NPAs) के बारे में और Assets Reconstruction Companies (ARCs) के बारे में तो समझ रहे हैं, लेकिन जो Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) हैं, जिनकी हालत बहुत ही खराब है, उनके बारे में हम क्या करने जा रहे है? पिछले दो सालों में कितनी सिक यूनिट्स हुई हैं और उनको रिवाइव करने के लिए क्या आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं?

श्री कलराज मिश्रः मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो मूल प्रश्न पूछा है, उस में इन्होंने 'details of works being undertaken by the National Small Industries Corporation (NSIC), in Gujarat' के बारे में पूछा है। दूसरा प्रश्न माननीय केशव राव जी का है, जिसे आप पूछ रहे हैं। ज्यादा उपयुक्त होता यदि आप अपने प्रश्न पर ही प्रति-प्रश्न पूछते।

SHRI AHMED PATEL: It is related to this only. It is about Micro, Small and Medium Enterprises. मैंने आपसे केवल यही पूछा है कि कितनी सिक यूनिट्स हैं और उनको रिवाइव करने के लिए क्या आप कोई कदम उठाने जा रहे हैं या नहीं?

श्री कलराज मिश्रः ठीक है, मैं बता रहा हूं, लेकिन आपने अपना सवाल NSIC के बारे में पूछा था और आपने यह पूछा था कि गत दो वर्षों में NSIC के द्वारा कितने उद्योगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया? आपका मूल प्रश्न यह था और उसी के बारे में हमने तैयारी की थी। फिर भी आपने जो प्रश्न पूछा है कि कितनी सिक इंडस्ट्रीज़ हैं, मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि Reserve Bank of India की तरफ से जो आंकड़े आए हैं, उनके अनुसार यह संख्या 5,77,000 हैं। MSMEs में, हर सिक यूनिट, जो रिवाइव हो सकती है, उनमें से लगभग हरेक को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। उस दिशा में हमने हर संभव प्रयत्न किया है।

महोदय, जो NPA होने के क्रम में हैं, उनके लिए भी हमने प्रयत्न किया है। उनके लिए हमने 'a framework for revival and rehabilitation of the enterprises' का कार्य किया है। इसमें जो NPA होने वाली यूनिट होगी, जो सिक होगी और रिवाइव होने की प्रक्रिया में होगी, ये दोनों बैंक को आवेदन करेंगे और बैंक उस आवेदन पर विचार करेगा। Reserve Bank of India की तरफ सें हमें यह निर्देश आया है कि जो यूनिट्स 10 लाख रुपये तक की हैं, उनके बारे में बैंक मैनेजर स्वयं विचार कर लेगा। इससे ऊपर की यूनिट्स के बारे में एक कमेटी बनेगी, जिस कमेटी का नाम होगा— 'Corrective Action Plan Committee'. वह कमेटी इस बात पर विचार करेगी कि वह wilfully NPA हो रहा है या सचमुच में है। ऐसे में बैंक के द्वारा उसे अवसर प्रदान किया जाएगा कि इतने दिनों के अन्दर वह अपनी यूनिट को restructure कर ले। इनके revival की दृष्टि से हमने ये सभी प्रयत्न किए हैं।

दूसरा, सिक होने की ज्यादा स्थिति वहां होती है, क्योंकि इनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में बहुत अधिक जटिलताएं हैं। उन जटिलताओं को दूर करने के लिए, ताकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्दी हो सके, इसके लिए वेब पोटर्ल के आधार पर हमने एक नया उद्योग आधारित मेमोरेंडम फॉर्म कायम किया है। जहां अभी तक 230 पेज पढ़कर क्वेरी की जाती थी, वहां केवल एक पेज में 20 प्वाइंट्स दिए गए हैं, जो ऑनलाइन हैं। उन्हें क्लिक करने के बाद, जिसे रजिस्ट्रेशन करवाना है, वह उस फॉर्म को भरेगा और उसको फिल करने के बाद within five minutes he would get the Registration Number.

मान्यवर, मुझे आपको यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस में अब तक 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।

श्री अहमद पटेलः सर, हम लोग 'start-ups' की बात कर रहे हैं। स्कीम भी है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि जो 'start-ups' है, उनसे एमएसएमई, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को कोई फायदा होगा या नहीं अथवा क्या इसके लिए कोई सेपरेट फंड हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं? खास तौर पर जो महिलाएँ हैं, जो लघु उद्योग शुरू करने जा रही हैं, उनके लिए उनको फाइनेंशियली मदद करने के लिए क्या कोई स्कीम है?

श्री कलराज मिश्रः सर, जो एमएसएमई की डेफिनिशन है, उसके अंतर्गत स्वयं हमने एक लिमिट सुनिश्चित की है। उस में 25 लाख तक माइक्रो इंडस्ट्रीज़ की लिमिट है, 5 करोड़ तक

स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की है और 10 करोड़ तक की मीडियम इंडस्ट्रीज़ की है। माइक्रो इंडस्ट्रीज़ को एनकरेज़ करने की दृष्टि से हमारी तरफ से लगातार प्रयास चलते रहे हैं और उस में 1 करोड़ तक का लोन जो होगा, वह collateral-free loan होगा और उस लोन के आधार पर हम उनको उद्योग लगाने की दृष्टि से प्रेरित करते हैं। उस में अगर बैंक की तरफ से और परेशानी होती है, तो एमएसएमई में एक 'क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड', जैसा आपने बताया, 'क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड' के माध्यम से थर्ड पार्टी गारंटी लेने की दृष्टि से सुनिश्चित किया है और उसके आधार पर हम उनको लोन दिलवाते हैं, जिसके कारण माइक्रो इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को लोन लेने में सुविधा हो। उसको SIDBI के द्वारा पूरा किया जाता है।

महिलाओं की दृष्टि से और एससी/एसटी की दृष्टि से हमने विशेष प्रयास किया है। Prime Minister Employment Generation Programme के अंतर्गत रूरल क्षेत्र में जो विलेज इंडस्ट्री होगी, वहां जनरल लोगों के लिए 25 परसेंट की सब्सिडी है, महिलाओं के लिए 35 फीसदी की है। शहरों में सामान्य लोगों के लिए 15 फीसदी की है और महिलाओं के लिए 25 परसेंट की है। इस तरह से उनको इनकरेज करने का हमारा प्रयास है। इसी ढंग से हम वहां इम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के अंतर्गत महिलाओं को भी जोड़ने जा रहे हैं, एससी/एसटी को जोड़ा है। उसमें earnest money बगैर टेंडर दे सकेंगे और टेंडर लेने के बाद L1+15 परसेंट उसकी सुविधा दी जाएगी।

श्री संजय राउतः सर, इस देश में अगर उद्योग बढ़ेगा, तो रोजगार बढ़ेगा। उद्योग बढ़ाने के लिए 'मेक इन इंडिया' जैसे प्रोजेक्ट्स हमारे मुम्बई में भी शुरू हो गए हैं। लेकिन सर, 'मेक इन इंडिया' से 30 लाख रोजगार निर्माण होने की बात सरकार की तरफ से, प्रधान मंत्री जी की तरफ से भी महाराष्ट्र में की गई, लेकिन वह अभी कागज पर है। एमओयू हो गये हैं। सबसे ज्यादा रोजगार इन छोटी इंडस्ट्रीज़, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इन इन्डस्ट्रीज़ की तरफ से उपलब्ध होता है।

श्री सभापतिः आपका प्रश्न क्या है?

श्री संजय राउतः सर, मेरा प्रश्न है कि सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि NSIC के माध्यम से गुजरात को 2013-14 में ₹ 50.80 crores, 2014-15 में ₹ 116.16 crores और 2015-16 में ₹ 89.16 crores as a credit support for the small industry मिला है। मेरा प्रश्न है कि अब तक, 2016 तक, महाराष्ट्र सरकार को महाराष्ट्र में इस तरह से कितना क्रेडिट सपोर्ट for small industries, micro industries and medium industries मिला है?

श्री सभापतिः सवाल गुजरात पर है।

श्री संजय राउतः सर, यह देश की बात है।

श्री कलराज मिश्रः सर, मैं बताता हूँ। अब तक के हिसाब से, जबकि हमारी तरफ से धन का कोई आवंटन नहीं होता है, स्कीम्स के हिसाब से होता है। स्कीम्स के हिसाब से हमसे गुजरात के बारे में सवाल पूछा गया था, जिसका उत्तर दिया गया है। महाराष्ट्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करके मैं आपके पास भेज दूँगा।

SHRI PRAVEEN RASHTRAPAL: Sir, the hon. Minister will appreciate the fact that Ahmedabad was once called the 'Manchester of India'. There were 60 textile mills

in Ahmedabad itself. Now, there is none. Only one NTC mill is working. Thousands of educated and uneducated youth are unemployed and we are all waiting for small scale industries to start, but, as admitted by the Ministry, only recently, the NSIC has started one livelihood business at Rajkot. Now, Gujarat has got many cities. Urbanisation in Gujarat is the highest in India. If the ratio of rural and urban areas is 70:30 in India, in Gujarat, 40 per cent areas are urban areas. Unemployed youth is there. There is no name of Rajkot, Bhavnagar, Jamnagar, Baroda and Surat. Only one city's name is given. So, I want to know from the hon. Minister as to how he is going to take care of all urban cities of Gujarat where educated and uneducated youth unemployment is highest.

श्री कलराज मिश्रः मान्यवर, यह जो प्रश्न है, एन.एस.आई.सी. के बारे में, यह केवल स्कीम को उद्योगों के विकास की दृष्टि से लागू करती है। उसके लिए एन.एस.आई.सी. का काम है कच्चे माल को देना, एन.एस.आई.सी. का काम है सहायता प्रदान करना, एन.एस.आई.सी. का काम है जो टैंडर और मार्केट कंसोर्टियम है, उसको प्रदान करना, टेक्नीकल असिस्टेंस प्रदान करना, परफामैंस रेटिग की दृष्टि से करना और साथ ही साथ जो अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं उद्यमियों को, उनको बैंक से कैसे राहत प्रदान की जाए, इस दृष्टि से विचार करना। इस हिसाब से केवल हमने एक नई स्कीम— ASPIRE, चालू की है। — A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry and Entrepreneurship. इस हिसाब से एक इन्क्यूबेशन सेंटर राजकोट में खुला। यह स्कीम जो अभी प्रारम्भ हुई है, जिसको सात-आठ महीने पहले प्रारम्भ की है, उस स्कीम के अंदर हमने लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेटर सेंटर, राजकोट के अंतर्गत खोला है और उसका बड़ा लाभ है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की दृष्टि से उसका बड़ा उपयोग होगा। हम इंडस्ट्री खोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। एन.एस.आई.सी. केवल सहयोग प्रदान करता है प्रारम्भ से ही।

श्री लाल सिंह वडोदियाः माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि खादी ग्रामोद्योग एम.एस.एम.ई. के अंदर आता है और गुजरात में खादी और ग्रामोद्योग की स्थिति कुछ नाजुक है। तो खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार ने एम.एस.एम.ई. के द्वारा कोई योजना बनाई है?

श्री कलराज मिश्रः मान्यवर, यह भी मूल प्रश्न से तो अलग है, लेकिन तो भी इसमें हमने कई इनीशिएटिव लिए हैं खादी ग्रामोद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, पी.एम. के माध्यम से।

Impact of Swachh Bharat Abhiyan

*137. SHRI BASAWARAJ PATIL: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the impact of Swachh Bharat Abhiyan all over India; and

(b) the steps taken by the Government to make India as Swachh Bharat before Gandhiji's 150th birth anniversary in different fields through different departments?